RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 22 SEPTEMBER TO 28 SEPTEMBER 2021 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 07 ■ अंक 4 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

ओएनजीसी विदेश लि. ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के तेल ब्लॉक में खोज कार्य को और समय मांगा Page 2

जीएसटी में शामिल नहीं होगा पेट्रोल-डीजल Page 5

फॉरएवरमार्क का अवंती जूलरी कलेक्शन लांच Page 7

editoria!

बेरोजगारी की चुनौती

नैशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (एनएसओ) की ओर से जारी किए गए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.3 फीसदी रही। ये लगातार तीसरी तिमाही रही, जिसमें बेरोजगारी दर दस फीसदी से ऊपर दर्ज की गई, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन तीनों तिमाहियों के दौरान लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां करीब-करीब ठप हो चुकी थीं। उस असाधारण स्थिति से आहिस्ते आहिस्ते उबरने की कहानी इन आंकड़ों में देखी जा सकती है। इससे ठीक पहले की यानी जुलाई से सितंबर 2020 की तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर 13.3 फीसदी थी। हालांकि इससे आगे की अवधि भी कम उतार-चढ़ाव वाली नहीं रही। कठिन दौर को पीछे छोड़कर जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई दिखने लगी थी, तभी कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर ने एक बार फिर जैसे सब तहस-नहस कर दिया। वैसे पहले दौर का अनुभव काम आया और महामारी का मुकाबला करते हुए भी सरकारों ने देशव्यापी लॉकडाउन के बदले विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक स्थानीय और सीमित लॉकडाउन की नीति अपनाई, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी जहां तक संभव हो सका, चलती रहीं। इसी का परिणाम था कि दूसरी लहर का कहर थमने के बाद इकॉनमी को दोबारा संभलने में पिछली बार जितनी कठिनाई नहीं हुई। इसी शुक्रवार को जारी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन (आईआईपी) के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। इसके मुताबिक जुलाई के फैक्ट्री उत्पादन में 11.5 फीसदी की बढ़ोतरी को भले इस अर्थ में भ्रामक कहा जाए कि यह पिछले साल के लो बेस इफेक्ट की वजह से बेहतर दिख रही है, लेकिन यह तथ्य जरूर उत्साह बढ़ाने वाला है कि औद्योगिक उत्पादन महामारी से पहले वाले स्तर को छूने लगा है। निश्चित रूप से यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती का संकेतक है। मगर असली पेच बेरोजगारी पर ही फंसा हुआ है। सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में भी बेरोजगारी दर 8.3 फीसदी रही। पिछले महीने देश भर में 19 लाख लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा। जाहिर है, इस स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति तो कम होती ही है, उनकी क्रय-इच्छा पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आसपास के लोगों की नौकरियां जाते देख जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं, उनका मन भी आशंकित हो जाता है। नतीजतन, जरूरत और क्षमता होते हुए भी वे खरीदारी की योजना स्थगित कर देते हैं। मांग की कमी की समस्या से जूझती अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले घोषित मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के पीछे निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास दर तेज करने और रोजगार के मौके बनाने की मंशा है। लेकिन सही मंशा काफी नहीं है। चुनौती तो इस मंशा को अमली जामा पहनाते हुए जमीन पर उतारने की है।

फिर उछला कच्चा तेल

अपने यहां 17वें दिन भी फेरबदल नहीं

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका में कच्चे तेल की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 17 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान वहां के क्रूड इंवेंट्री से 6.108 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ। इससे पहले के सप्ताह में भी 5.437 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ था। हालांकि, 17 सितंबर को समाप्त सप्ताह के लिए विश्लेषकों ने 2.400 मिलियन बैरल के ड्रॉ का अनुमान लगाया था। अनुमान से भी अधिक खपत की वजह से मंगलवार को कच्चे तेल का बाजार (Crude Oil Market) एक बार फिर से चढ़ गया। लेकिन, भारत में देखें तो यहां सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले शिक्षक दिवस (05 सितंबर 2021) के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे की कमी हुई थी। दिल्ली के बाजार में मंगलवार को इंडियन ऑयल (IOC) के पंप पर पेट्रोल प्रति लीटर 101.19 रुपये पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88.62 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है।

इस साल मई से जुलाई के बीच 11.52 रुपये महंगा हो चुका है पेट्रोल

इस साल की पहली तिमाही के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च और अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसलिए, उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन, बीते चार मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी। कभी लगातार तो कभी ठहर कर, 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। हालांकि, हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोलियम मंत्री बनने के बाद बीते 18 जुलाई से इसके दाम स्थिर थे। रक्षा बंधन के दिन, इसके दाम में महज 20 पैसे की कमी की गई थी। उसके दो दिन बाद भी 15 पैसे की कमी हुई है। उसके बाद एक सितंबर और पांच सितंबर को इसके दाम फिर 15-15 पैसे घटे।

पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा सस्ता हुआ है डीजल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल भले ही सस्ता बिक रहा हो, लेकिन यहां सरकारी तेल कंपनियां उस हिसाब से कीमतों में कमी नहीं कर रही हैं। वैसे भी डीजल महंगा ईंधन होने के बावजूद भारत में यह पेट्रोल के मुकाबले सस्ता बिकता है। इस साल के शुरूआती महीनों के दौरान कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस दौरान 41 दिनों तक डीजल के दाम में कोई फेरदबल नहीं हुआ था। उस समय डीजल के दाम में अंतिम कमी बीते 15 अप्रैल को हुई थी। उस समय 14 पैसे की कमी हुई थी। लेकिन बीते 4 मई से इसमें जो ठहर-ठहर कर बढ़ोतरी हुई, उससे डीजल 9.08 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। उसके बाद बीते 16 जुलाई से इसके दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। बीते 18 अगस्त से 20 अगस्त तक इसकी कीमतों 20 पैसे प्रति लीटर की रोजाना कमी हुई है। इसके बाद रक्षा बंधन के दिन भी दाम में इतनी ही कमी हुई थी। उसके दो दिन बाद भी यह 15 पैसे सस्ता हुआ था। बीते एक सितंबर के 15 पैसे और पांच सितंबर के 15 पैसे की कमी को जोड़ लिया जाए तो पिछले एक पखवाड़े में अब तक डीजल 1.25 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो चुका है।

कच्चे तेल के बाजार में फिर उछाल

अमेरिका में कच्चे तेल की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीच्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 17 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान वहां के क्रूड इंवेंट्री से 6.108 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ। इससे पहले के सप्ताह में भी 5.437 मिलियन बैरल क्रूड का ड्रॉ हुआ था। हालांकि, 17 सितंबर को समाप्त सप्ताह के लिए विश्लेषकों ने 2.400 मिलियन बैरल के ड्रॉ का अनुमान लगाया था। अनुमान से भी अधिक खपत की वजह से मंगलवार को कच्चे तेल का बाजार एक बार फिर से चढ़ गया। कल अमेरिकी बाजार में ब्रेंट क्रूड 74.36 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ जो कि पिछले दिन के मुकाबले 0.44 डॉलर अधिक है। डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 01.27 डॉलर बढ़ कर 70.56 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

देश में कच्चे तेल का उत्पादन अगस्त महीने में 2.3 प्रतिशत घटा, गैस उत्पादन में बढ़त

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में अगस्त माह के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 2.3 प्रतिशत घट गया। हालांकि, रिलायंस-बीपी के केजी-डी6 फील्ड से होने वाले उत्पादन के कारण इस दौरान गैस उत्पादन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। सरकार के द्वारा बुधवार को जारी आंकड़े से यह जानकारी मिली। आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के तेल एवं गैस क्षेत्रों से उत्पादन कम होने से अगस्त महीने में कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 25.1 लाख टन रहा। भारत अपनी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिये 85 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर है। इसको देखते हुए सरकार लंबे समय से घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। प्राकृतिक गैस का उत्पादन इस अवधि में 20 प्रतिशत बढ़कर 2.9 अरब घन मीटर रहा। इसका कारण निजी कंपनियों के गैस क्षेत्रों से उत्पादन में 186 प्रतिशत की वृद्धि है। आंकड़े के साथ जारी बयान के अनुसार, "गैस उत्पादन में वृद्धि का कारण नये क्षेत्रों डी-34 और केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 के उप-क्षेत्रों (केजी-डी6) से उत्पादन है। यहां उत्पादन क्रमशः दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में शुरू हुआ।" रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसकी भागीदार ब्रिटेन की बीपी पीएलसी केजी-डी6 फील्ड का परिचालन करती है। देश की सबसे बड़ी तेल एवं गैस उत्पादक ओएनजीसी का कच्चे तेल का उत्पादन 4 प्रतिशत घटकर 16 लाख टन और गैस 9 प्रतिशत कम होकर 1.7 अरब घन मीटर रहा। आंकड़े के अनुसार ईंधन मांग बढ़ने के साथ तेल रिफाइनरियों ने अगस्त महीने में अधिक कच्चे तेल को प्रोसेस किया। इस अवधि में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग सालाना आधार पर 14.17 प्रतिशत बढ़कर 1.84 करोड़ टन रही। वहीं खनन मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के महीने में खनिज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत बढ़ा है।

शुरु हुआ नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, एक ही जगह कई काम निपटा सकेंगे कारोबारी और निवेशक

फिलहाल 18 केन्द्रीय विभाग और 9 राज्य शामिल

14 अन्य केन्द्रीय विभाग और 5 राज्यों को दिसंबर, 2021 तक होगें शामिल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

उद्योगों के लिये देश में कारोबार करने को और सुगम बनाने के लिये देश में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत कर दी गयी है। सिस्टम की शुरुआत करते हुए उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और मंजूरी के लिये सरकारी विभागों में लगने वाली दौड़ से अब कारोबारियों और निवेशकों को मुक्ति मिलेगी। इस पोर्टल में फिलहाल 18 केन्द्रीय विभाग और 9 राज्य शामिल हैं, वहीं 14 अन्य केन्द्रीय विभाग और 5 राज्यों को दिसंबर, 2021 तक इसमें जोड़ लिया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 'एंड टू एंड' सुविधा के माध्यम से कोई भी एक क्लिक के जरिये जरूरी काम निपटा सकेगा। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी क्योंकि सभी जानकारियां डैश बोर्ड पर उपलब्ध होंगी। सिस्टम के जरिये पंजीकरण, राज्य पंजीकरण, ई-कम्युनिकेशंस, नो योर अप्रूवल (केवाईए) जैसी सुविधायें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद तेजी से सुधार होने के कारण हम सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से पुनः एक बनने की राह आ गए है। श्री गोयल ने कहा की एनएसडब्ल्यूएस हमारी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआई योजना जैसी अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। मेक इन इंडिया, मेक फोर दा वर्ल्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने अनेक पहल शुरू की है, जिनमें प्रमुख उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई और भारत औद्योगिक भूमि बैंक प्रणाली शामिल हैं। 27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल खर्च के साथ 13 क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं की घोषणा की गई है। केन्द्रीय बजट भाषण 2020 में वित्त मंत्री ने महत्वाकांक्षी निवेश मंजूरी सेल (आईसीसी) की घोषणा की थी। इस सेल का ऐलान निवेशकों को 'एंड टू एंड' सुविधा सहायता प्रदान करने के लिये किया गया था। इसके बाद डीपीआईआईटी ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) के रूप में एक पोर्टल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की। नये सिस्टम से आवेदन कर्ता को एक ही बार अपने दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे और बार बार अलग अलग विभाग में अलग अलग दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी।

ओएनजीसी विदेश लि. ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के तेल ब्लॉक में खोज कार्य को और समय मांगा

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) की विदेशी इकाई ओएनजीसी विदेश लि. ने विवादित दक्षिण चीन सागर में वियतनाम से मिले तेल ब्लॉक में खोज कार्य को लेकर सातवीं बार लाइसेंस अवधि दो साल बढ़ाने की मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) ने ब्लॉक-128 में तेल और गैस का पता लगाने के लिये दो साल की अवधि और बढ़ाये जाने की मांग की है। इस ब्लॉक के लिये लाइसेंस अवधि 15 जून, 2021 तक वैध थी।

भारत दक्षिण चीन सागर में रणनीति हित बनाये रखना चाहता है। वहीं वियतनाम चाहता है कि भारतीय कंपनी विवादित जल क्षेत्र में चीनी हस्तक्षेप का मुकाबला करे। ओवीएल ने मई 2006 में पेट्रो वियतनाम के साथ उत्पादन साझेदारी समझौता (पीएससी) किया था। यह समझौता गहरे जल क्षेत्र में स्थित ब्लॉक-128 में तेल की स्थिति का पता लगाने के लिये था। यह

क्षेत्र वियतनाम में फुकान बेसिन में 7,058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। निवेश लाइसेंस 16 जून 2006, को जारी होने के साथ पीएससी अमल में आया।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ब्लॉक में तेल एवं गैस की खोज जारी रखेगी, जो पानी के भीतर 200 से 2,000 मीटर की गहराई में है। अधिकारियों के अनुसार ब्लॉक में अब तक कोई खोज नहीं हो पायी है। एक अधिकारी ने कहा, ''हम उम्मीद करते हैं कि वे पीएससी 15 जून, 2023 तक बढ़ाने को सहमत होंगे।'' उसने कहा कि वियतनाम की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रो वियतनाम बेहतर भूगर्भीय समझ के लिये 'पेट्रोलियम सिस्टम मॉडलिंग' और अन्य संबंधित अध्ययन को लेकर ब्लॉक 128 के समीप के क्षेत्र से संबंधित तकनीकी आंकड़े साझा करने को सहमत है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि दो साल पहले हमने ब्लॉक में एक कुएं की खुदाई की थी लेकिन वह लक्षित गहराई तक नहीं पहुंच सका। इसे कुएं को फिर से खोदा जाना है। उसने कहा, ''अगर हम कुंए की खुदाई नहीं करते हैं, हमें जुर्माना देना होगा।''

1 अक्टूबर से बदल जाएगा कार्ड पेमेंट का तरीका, बिना SMS भेजे बैंक नहीं काट सकेंगे पैसा

नई दिल्ली। एजेंसी

सितंबर महीने के खत्म होने में बहुत कम वक्त बचा है। नए महीने की शुरुआत के सत ही कई चीजें बदल जाएंगी। बैंक की छुट्टी से लेकर चेक पेमेंट तक के नियम में बदलाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में एक बदलाव कार्ड पेमेंट को लेकर भी होने जा रहा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के पेमेंट के नियम में बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से बैंक बिना एसएमएस भेजे आपका ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते हैं।

1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम 1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट का नियम बदल जाएगा। अगले महीने से ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए महीने के साथ ऑटो पेमेंट का नया सिस्टम लागू होगा। नए सिस्टम के तहत बैंक, फाइनेंस कंपनी या पेटीएम, फोनपे जैसी कंपनियां बिना आपको सूचित किए ऑटो डबिट नहीं कर सकती है। आपकी ईएमआई या बिल का ऑटो पेमेंट बिना आपकी अनुमति या पूर्व जानकारी के नहीं होगा। बैंकों को पेमेंट काटने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी।

RBI ने बदला नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सिस्टम में बदलाव किया है। नए बदलाव के मुताबिक हर बार ऑटो पेमेंट के लिए बैंक को ग्राहकों से अनुमति देनी होगी। RBI के नए नियम के मुताबिक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या UPI के पेमेंट के अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। नए नियम के तहत अब आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड में बिना आपकी अनुमति के पैसा नहीं कटेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर बंक में अपडेट करवाना होगा। बैंक खाते में नंबर अपडेट होने के बाद ही आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर ऑटो डेबिट से पहले एश्ए आएगा।

5 दिन पहले मिलेगा मैसेज आरबीआई के नए नियम के मुताबिक पेमेंट की डेट से 5 दिन पहले ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। पेमेंट से 24 घंटे पहले दोबारा से रिमाइंडर भेजा जाएगा। आपको पेमेंट से पहले ऑप्ट आउट या पार्ट-पे का ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही 5000 रुपए से अधिक के पेमेंट के लिए ओटीपी को अनिवार्य कर दिया हैं।

भारत में अप्रैल-जून तिमाही में छतों पर लगाये जाने वाली सौर क्षमता में 521 मेगावाट वृद्धि

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने इस साल अप्रैल-जून के दौरान छतों पर लगायी जाने वाली सौर क्षमता में 521 मेगावाट की वृद्धि की। किसी एक तिमाही में यह अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है। स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी मेरकॉम इंडिया की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च की 2021 की दूसरी तिमाही की 'रूफटॉप सोलर मार्केट रिपोर्ट' के अनुसार भारत ने इस साल अप्रैल-जून के दौरान छतों पर लगायी जाने वाली सौर क्षमता में 521 मेगावाट का इजाफा किया। यह तिमाही आधार पर 53 प्रतिशत अधिक है। इस साल पहली तिमाही जनवरी-मार्च में 341 मेगावाट क्षमता के संयंत्र छतों पर लगाये गये थे। वहीं सालाना आधार पर छतों पर लगाये गये सौर संयंत्र 517 प्रतिशत अधिक हैं। पिछले साल 2020 के अप्रैल-जून के दौरान 85 मेगावाट क्षमता के संयंत्र लगाये गये थे। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिये राज्यों के स्तर पर लगाये गये 'लॉकडाउन' के बावजूद पिछली तिमाही के मुकाबले क्षमता में इजाफा हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस बार 'लॉकडाउन' काफी लक्षित था और उद्योग इस बार पहले से तैयार था। इससे परियोजना लगाने के काम पर बहुत कम असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 2021 की पहली छमाही जनवरी से जून में छतों पर 862 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाये गये। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 210 प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं 'लॉकडाउन' से प्रभावित 2020 में कुल स्थापित 719 मेगावाट क्षमता से भी अधिक है। मेरकॉम के अनुसार 2021 की दूसरी तिमाही के अंत में छतों पर लगाये गये कुल सौर संयंत्रों की क्षमता 6,100 मेगावाट पहुंच गयी।

सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2020-21 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 148.3 अरब डॉलर पर: आरबीआई सर्वे

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2020-21 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 148.3 अरब डॉलर रहा। निर्यात में भारतीय कंपनियों से संबद्ध विदेशी इकाइयों की सेवाएं शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के सोमवार को जारी सर्वे से यह जानकारी मिली। आरबीआई ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाओं के निर्यात को लेकर 2020-21 का सालाना सर्वे जारी किया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार,

''भारत का सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात (वाणिज्यिक मौजूदगी के जरिये निर्यात को छोड़कर) 2020-21 में सालाना आधार पर चार प्रतिशत बढ़कर 133.7 अरब डॉलर रहा। विदेशी संबद्ध इकाइयों की वाणिज्यिक मौजूदगी के जरिये सॉफ्टवेयर निर्यात 2020-21 में 14.6 अरब डॉलर रहा। इस मामले में सबसे बड़ा गंतव्य अमेरिका है। आरबीआई के अनुसार भारतीय कंपनियों की संबद्ध विदेशी इकाइयों समेत कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात 2020-21 में 2.1 प्रतिशत बढ़कर 148.3 अरब डॉलर रहा। कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में कंप्यूटर सेवाओं और आईटी संबद्ध सेवाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 65.3 प्रतिशत और 34.7 प्रतिशत रही। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबद्ध सेवाओं (आईटीईएस) के निर्यात में बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) सेवाओं का दबदबा रहा। केंद्रीय बैंक ने कहा, ''सॉफ्टवेयर निर्यात के लिये 54.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख गंतव्य अमेरिका रहा। यूरोप की हिस्सेदारी 30.1 प्रतिशत रही। इसमें करीब आधी हिस्सेदारी ब्रिटेन की थी।

जीएसटी में शामिल नहीं होगा पेट्रोल-डीजल

राज्यों ने किया विरोध

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन राज्यों ने इसका विरोध किया। सीतारमण ने कहा कि यह मुद्दा केरल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में आया। जीएसटी के सदस्यों ने इसका विरोध किया। काउंसिल ने माना कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है।

सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रॉडक्टस को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। यह तय हुआ है कि काउंसिल को यह बात केरल हाई कोर्ट को बतानी चाहिए कि इस मामले पर चर्चा हुई है। काउंसिल ने महसूस किया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का यह सही समय नहीं है।बैठक में जोमैटो जैसी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यात्री परिवहन से जुड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया। उन पर 1 जनवरी, 2022 से 5 प्रतिशत जीएसटी लेने का निर्णय किया गया।

16 करोड़ की दवा जीएसटी से मुक्त

उन्होंने कहा कि काउंसिल ने कोरोना महामारी की दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी है। यह छूट केवल दवाओं पर बढ़ाई गई है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर नहीं। कुछ चिकित्सा उपकरण पर रियायती कर की व्यवस्था 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। Amphotericin B और ऊदमर्तैर्ल्ले पर 31 दिसंबर तक कोई जीएसटी नहीं लगेगा। काउंसिल ने साथ ही मस्कुलर एट्रॉफी के इलाज में काम आने वाली दवाओं ैंदुतहेर्ई और न्नूतेज्द को भी जीएसटी में छूट देने का फैसला किया है। ये बहुत खास दवाएं हैं जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये है। यह छूट पर्सनल यूज के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर मिलेगी। अब तक इन पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था। कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे कीट्रूडा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% की गई है।

बायोडीजल पर घटा जीएसटी

सीतारमण ने कहा कि लीज पर लेने के लिए विमानों के आयात पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। काउंसिल ने साथ ही रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है। बायोडीजल पर जीएसटी की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने गुड्स कैरीज के लिए राज्यों द्वारा ली जाने वाली नैशनल परमिट फीस में छूट देने का फैसला किया है।पोषक तत्वों से युक्त चावल केरनेल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया। काउंसिल ने सभी प्रकार के पेन (कलम) पर 18 प्रतिशत की एकल दर से जीएसटी जबकि विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 12 प्रतिशत माल एवं सेवा कर लगाने का निर्णय किया गया है। सीतारमण ने कहा कि परिषद ने जूता-चप्पल और कपड़ों पर 1 जनवरी, 2022 से उल्टा शुल्क ढांचे (कच्चे माल पर कम और तैयार माल पर अधिक शुल्क) को ठीक करने को लेकर सहमति जताई है।

20 महीने बाद पहली फिजिकल बैठक

सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में गुजरात को छोड़कर लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हुए। इसमें केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के बाद आमने-सामने बैठकर हुई यह परिषद की पहली बैठक थी। इस तरह की आखिरी बैठक 20 महीने पहले 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। उसके बाद से परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रही थी। देश में जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई, 2017 से लागू हुई थी। जीएसटी में केंद्रीय कर मसलन उत्पाद शुल्क और राज्यों के शुल्क मसलन वैट को समाहित किया गया था। लेकिन पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, प्राकृतिक गैस तथा कच्चे तेल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसकी वजह यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को इन उत्पादों पर कर से भारी राजस्व मिलता है।

परिधान निर्माताओं का 1,000 रुपये तक के वस्त्रों पर 5 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखने का आग्रह

कोलकाता। एजेंसी

पश्चिम बंगाल कपड़ा उद्योग ने बुधवार को केंद्र सरकार से 1,000 रुपये मूल्य तक के कपड़ों पर 5 प्रतिशत जीएसटी बरकरार रखने का आग्रह किया है। उद्योग ने कपड़ों के मामले में उल्टा शुल्क ढांचा यानी कच्चे माल पर अधिक तथा तैयार सामान पर कम शुल्क व्यवस्था में सुधार किये जाने के जीएसटी परिषद के फैसले के बाद कर ढांचे में वृद्धि की आशंका को देखते हुए यह अनुरोध किया है। कपड़ा उद्योग इस बात से आशंकित है कि व्यवस्था में सुधार के साथ 1,000 रुपये तक मूल्य के परिधान पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा। उद्योग मंडल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग की इकाइयों ने केंद्रीय कपड़ा सचिव यू पी सिंह से कहा कि 1,000 रुपये तक के बिक्री मूल्य वाले परिधान पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत बना रहना चाहिए ताकि यह आम लोगों के लिये सस्ता बना रहे। उद्योग ने कहा कि अगर इस खंड में जीएसटी दर बढ़ती है, महामारी के समय में इसका असर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की 17 सितंबर को हुई 45वीं बैठक में जूता-चप्पल और कपड़ा क्षेत्र में उल्टा शुल्क ढांचा व्यवस्था में एक जनवरी, 2022 से सुधार लाने पर सहमति जतायी गयी।

कार्यक्रम में सिंह ने कहा कि सरकार चाहती है कि पूर्वी भारत कपड़ा क्षेत्र में विकसित हो और उद्योग को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना समेत अन्य कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए। इस पर उद्योग ने कहा कि पूर्वी भारत का कपास के मामले में दबदबा है और सिंह से अनुरोध किया कि वह पश्चिम बंगाल में बनने वाले होजरी पार्क को समर्थन दें जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे टूटा

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

विदेशी बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले 11 पैसे टूटकर 73.72 के स्तर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और विदेशी कोषों की लगातार आवक ने रुपये को बल दिया, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और अमेरिकी डॉलर सूचकांक में मजबूती के चलते भारतीय मुद्रा में गिरावट देखने को मिली। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 73.61 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.08 प्रतिशत बढ़कर 93.27 पर पहुंच गया।

अगरबत्ती आयात पर प्रतिबंध से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलाः गोयल

नयी दिल्ली। एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि अगरबत्ती आयात पर प्रतिबंध लगाये जाने से बड़े पैमाने पर इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद मिली है। सरकार ने अगस्त 2019 में चीन और वियतनाम जैसे देशों से अगरबत्ती के आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की रिपोर्ट के बीच अगरबत्ती और इसी तरह के अन्य उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इन सामानों के आयातकों को सरकार से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। गोयल ने त्रिपुरा में 'अगरवुड' (सुगंधित लकड़ी) से बने उत्पादों पर क्रेता-विक्रेता बैठक में कहा कि आयात पर प्रतिबंध ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद की। आगे जाकर हम सुगंधित लकड़ी (अगरबत्ती, इत्र जैसे सुगंधित उत्पाद बनाने में उपयोग) की खेती बढ़ा सकते हैं और फिर हम इसके आयात को भी रोक सकते हैं तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकते हैं।'' 'अगरवुड' चिप्स और उसके उत्पादों का वैश्विक व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर का है। उन्होंने यह भी कहा कि 'ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन' की मदद से रबर की खेती बढ़ाने के लिए योजना तैयार की गयी है।

कोविशील्ड को मान्यता लेकिन ब्रिटेन की सूची में भारत का नाम नहीं, अब क्या बोल रहा यूके

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रिटेन ने अपने यात्रा नियमों में बदलाव करते हुए भारत में निर्मित कोरोना रोधी वैक्सीन 'कोविशील्ड' को स्वीकृति दे दी है। लेकिन, बिना क्वारंटीन के यात्रा करने वाली 17 देशों की सूची में भारत का नाम अभी भी नहीं है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को इस फैसले से कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। उन्हें कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक लगाने के बावजूद 10 दिन क्वारंटीन रहना ही होगा। ब्रिटेन के उच्चायोग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम इसे लेकर भारत सरकार के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं कि हम किस तरह उन लोगों तक ब्रिटेन के वैक्सीन प्रमाणीकरण की मान्यता को विस्तारित कर सकते हैं, जिन्हें भारत में संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य निकाय की ओर से टीका लगाया गया है।

ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा, ब्रिटेन जितनी जल्दी हो सके अंतरराष्ट्रीय यात्रा को फिर से खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घोषणा सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए लोगों को सुरक्षित और अधिक स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए एक और कदम है। ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा, हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं, ताकि ब्रिटेन के सर्टिफिकेशन सिस्टम का दायरा बढ़ाने का रास्ता तलाश सकें।

मुख्य मुद्दा टीका प्रमाणन का है न कि कोविशील्ड टीके का

ऐसा समझा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने नई गाइडलाइन में भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर आशंका जाहिर की है। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि मुख्य मुद्दा टीका प्रमाणन का है न कि कोविशील्ड टीके का। भारत और ब्रिटेन इस मुद्दे का परस्पर हल ढूंढने के लिए संवाद कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश, जो 4 अक्तूबर से प्रभाव में आएंगे, का जिक्र करते हुए अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि लंदन को कोविशील्ड से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भारत में टीका प्रमाणन से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। नये दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा, ब्रिटेन आने वाले भारतीय यात्रियों को प्रशासन द्वारा तय गैर टीकाकृत नियमों का पालन करना ही चाहिए।

इन टीकों को किया सूचीबद्ध

परामर्श में कहा गया है, एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सजेवरिया और मॉडर्ना टाकेडा जैसे चार टीकों को स्वीकृत टीकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय यात्रियों को ब्रिटेन प्रस्थान से तीन दिन पहले एक कोविड-19 परीक्षण करना होगा और इंग्लैंड आगमन पर दो कोविड-19 परीक्षणों के लिए अग्रिम बुकिंग करनी होगी। इसके बाद इंग्लैंड पहुंचने पर यात्रियों को 10 दिनों के लिए अपने यात्री लोकेटर फॉर्म पर तय जगह पर पृथकवास में रहना होगा। पृथकवास के पांचवें दिन 'टेस्ट टू रिलीज' विकल्प के तहत 10-दिवसीय क्वारंटीन को जल्दी समाप्त करने की व्यवस्था दी गई है। खुद के खर्च पर पीसीआर परीक्षण कराना होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर क्वारंटीन से राहत मिल जाएगी।

भारत ने जताई थी नाराजगी

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को न्यूयार्क में ब्रिटेन की नवनियुक्त विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रूस के सामने कोविडशील्ड टीका लगवा चुके यात्रियों को पृथक-वास में भेजने का मुद्दा उठाया था। मंगलवार को यात्रा नियमों के संबंध में भारत को सूची से बाहर किए जाने पर विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगला ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर ब्रिटेन ने मांग नहीं मानी तो भारत भी कोई दूसरा रास्ता अपना सकता है।

पायलटों की तरह ट्रक ड्राइवरों को भी गाड़ी चलाने का समय तय होना चाहिए -परिवहन मंत्री

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने रोड एक्सिडेंट में कमी लाने के लिए कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए गाड़ी चलाने का समय तय किए जाने की वकालत की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कमर्शियल वाहनों में सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है, जिससे की ड्राइवर को नींद आते ही अलार्म बजने लगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सड़क परिषद (NRSC) की एक मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को कहा कि विदेशों में या यूरोपीय देशों के मानकों के हिसाब से कमर्शियल वाहनों में ऑन-बोर्ड स्लीप डिटेक्शन सेंसर लगाने की नीति पर काम किया जाए। इस मामले में NRSC की मीटिंग अब हर 2 महीने में होगी और अपनी रिपोर्ट शेयर करेगी। नितिन गडकरी ने थकान की वजह से होने वाली रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के मकसद से पायलटों के समान कमर्शियल वाहनों के ट्रक ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग के घंटे तय करने पर जोर दिया है। गडकरी ने कहा कि जिला सड़क समितियों की नियमित मीटिंग बुलाने के लिए सीएम और जिला कलेक्टरों को वो पत्र लिखेंगे। वहीं उन्होंने परिषद की मीटिंग हर महीने में करने के निर्देश दिए हैं। जिससे इस दिशा में काम में तेजी लाई जा सके।

किसानों ने 27 सितंबर को 'भारत बंद' का किया ऐलान, कई राजनीतिक पार्टियों सहित 100 ग्रुप होंगे शामिल

नयी दिल्ली। एजेंसी

संयुक्त किसान मोर्चा में किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के 27 सितंबर के भारत बंद में कई और किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं। इनकी संख्या करीब 100 बताई जा रही है। किसान संगठनों ने देशभर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए जोर-शोर से तैयारी की है। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों, किसान संघों, युवाओं, शिक्षकों, मजदूरों और अन्य सहित लगभग 100 संगठन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए 27 सितंबर के भारत बंद में शामिल होंगे। बयान में कहा गया है कि भारत बंद में कई किसान संगठनों के साथ-साथ कर्मचारी संघों, कारोबार संघों, कर्मचारियों और छात्र संघों, महिला संगठनों, ट्रांसपोर्टर संगठनों को शामिल किया जा रहा है। एसकेएम ने कहा कि बंद के दौरान आयोजित रैली में अधिक लोगों को शामिल करने के लिए किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है और साइकिल एवं मोटर साइकिल रैली का भी आयोजन किया जा रहा है। इस बीच केंद्र द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के प्रदर्शन के प्रदर्शन को बुधवार को 300 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी कर कहा कि यह आंदोलन देश के लाखों किसानों की इच्छाशक्ति और प्रतिबद्धता का सबूत है और ये और दृढ हुई है। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को बुधवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की। एआईबीओसी ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर उसके के साथ फिर से बातचीत शुरू करने और तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए भारत बंद के आह्वान का वामपंथी दलों ने समर्थन करने की घोषणा की है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), फॉरवर्ड ब्लॉक और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की गई है।

14 नवंबर को NDA प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगी लड़कियां!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक साल तक नहीं कर सकते इंतजार

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र सरकार के अनुरोध को बुधवार को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने NDA की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को इसी साल से शामिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 14 नवंबर को होने वाली ॅॅ प्रवेश परीक्षा में लड़कियां शामिल हो सकेंगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को ॅॅ प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी।

जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि वह महिलाओं को एनडीए में शामिल करने को एक साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया गया है, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है।

एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए प्रवेश परीक्षा को छोड़ने की अपील की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपकी समस्याओं को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं। परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र से इस अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है। पीठ ने कहा कि सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। हमें यकीन है कि वे इस आपातकालीन स्थिति से पार पाने में भी सक्षम होंगे।

ADB ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान घटाकर 10 प्रतिशत किया

नई दिल्ली। एजेंसी

एशियन डिवेलपमेंट बैंक ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 11 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है। ADB का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से हुए नुकसान का ग्रोथ पर असर पड़ेगा। इससे पहले अप्रैल में ADB ने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 11 प्रतिशत का अनुमान दिया था। ग्रोथ को लेकर ADB के एशियन डिवेलपमेंट आउटलुक अपडेट में कहा गया है, 'महामारी का असर अनुमान से पहले कम हो गया है और इससे कई राज्यों में लॉकडाउन में छूट दी गई है और ट्रैवलिंग शुरू हुई है। फाइनेंशियल ईयर की बाकी तीन तिमाहियों में इकोनॉमी में तेजी से रिकवरी होने की उम्मीद है। ADB का मानना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ घटकर 7.5 प्रतिशत पर आ सकती है। साउथ एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ इस वर्ष धीमी रहने का अनुमान है। हालांकि, अगले वर्ष इसके तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। इस रीजन में भारत के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और भूटान शामिल हैं। ADB ने कहा कि चीन में खपत में बढ़ोतरी अधिक नहीं होने के बावजूद ग्रोथ मजबूत रह सकती है। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में चीन की ग्रोथ 8.1 प्रतिशत और अगले फाइनेंशियल ईयर में 5.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चीन को एक्सपोर्ट बढ़ने और मौजूदा वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक फिस्कल मदद का फायदा मिल सकता है।

क्रिप्टो बाजार में बड़ी गिरावट

Bitcoin टूटकर 40000 डॉलर तक पहुंची

नई दिल्ली। एजेंसी

क्रिप्टो बाजार में अस्थिरता के बीच बिटकॉइन की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की कीमत बुधवार को 42,000 डॉलर के आस-पास है। अस्थिरता के चलते क्रिप्टो बाजार में भी गिरावट आई है और इसकी मात्रा भी कम हो रही है। क्रिप्टोकरेंसी का ग्लोबल मार्केट कैप बुधवार को 3 प्रतिशत नीचे गिरकर 1.83 ट्रिलियन डॉलर पर आ गया है और इसका वॉल्यूम लगभग 11 प्रतिशत तक नीचे गिर गया है।40,000 डॉलर तक लुढ़की दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले महीने 52 हजार डॉलर तक जाने वाली बिटकॉइन देर रात में 40,000 डॉलर तक लुढ़क गई थी लेकिन दिन में यह संभली है और 42,000 डॉलर के आस-पास कारोबार कर रही है। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि इसकी प्रतिद्वंद्वी ईथर भी खुद को 3000 डॉलर के निशान के ऊपर नहीं रख पाई और यह 2872 डॉलर पर कारोबार कर रही है। बीते 24 घंटे में इसने 4.25 प्रतिशत की गिरावट देखी है। पिछले सात दिनों में ईथर में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है। पिछले सप्ताह इसकी कीमत 4000 डॉलर के ऊपर बनी हुई थी लेकिन एक सप्ताह में ही यह 1000 डॉलर से नीचे गिर गई है। एवलांच ने देखी उछाल अगर किसी क्रिप्टोकरेंसी ने मार्केट में अपनी रैली बनाई है तो वह एवलांच है। एवलांच ने हाल ही में एक निजी बिकवाली को पूरा किया है जिसकी कीमत 23 करोड़ डॉलर बताई गई है। अपनी रैली के चलते एवलांच मार्केट कैप के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट की 11वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन गई है। 62.11 डॉलर की कीमत की कीमत पर कारोबार कर रही इस डिजिटल टोकन की कीमत में पिछले 24 घंटे में 10 गुना उछाल आया है। एवलांच इसी तरह चलती रही तो टॉप 10 क्रिप्टोकरेंसी की लिस्ट से डोजकॉइन को बाहर कर सकती है हालांकि अभी दोनों क्रिप्टोकरेंसी की मार्केट कैप में 13 अरब डॉलर का गैप बना हुआ है। डोजकॉइन में हल्की बढ़त वहीं एलन मस्क की पसंदीदा क्रिप्टोकरेंसी डोजकॉइन के हल्की बढ़त दर्ज की है। वर्चुअल करेंसी 1.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 0.203 डॉलर की कीमत पर कारोबार कर रही है। जबकि तीसरे नंबर की क्रिप्टोकरेंसी कार्डानो 2.05 डॉलर पर है जो कि 24 घंटे में 1.7 प्रतिशत की गिरावट पर है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि यह 2 डॉलर से नीचे नहीं गिरेगी। पिछले दिन के मुकाबले बिनांस कॉइन 2.39 प्रतिशत नीचे कारोबार करते हुए 354.09 डॉलर पर बनी हुई है। टॉप-5 में शामिल एक अन्य महत्वपूर्ण टोकन 1 डॉलर से नीचे आकर 0.92 पर कारोबार कर रहा है जो पिछले दिन के मुकाबले 2.19 प्रतिशत नीचे है।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

कोरोना वायरस से मौत पर मिलेगा 50 हजार रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से हुई मौतों पर 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की शिफारिश की है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों के परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि मुआवजे का भुगतान न केवल पहले हुई मौतों के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी किया जाएगा। बता दें कि कोरोना वायरस का शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग लंबे समय से हो रही थी। आखिरकार सरकार इसके लिए तैयार हो गई है।

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोरोना के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया था, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया था। मगर कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवजा तय करने के बारे में क्या किया गया है, कोर्ट को बताएं। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगली तारीख 23 सितंबर को कोर्ट के समक्ष यह ब्योरा रख दिया जाएगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा था कि वह यह देखे कि ऐसे मामलों में जहां कोरोना से परेशान होकर किसी ने आत्महत्या की हो तो उसे कोविड-19 से हुई मौत माना जाए। इस संबंध में राज्यों को नए दिशा-निर्देश दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण आत्महत्या करने वाले की मौत को कोविड से हुई मौत नहीं मानना स्वीकार्य नहीं है। उन्हें भी कोविड से हुई मौत का प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।

चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने से किया था इनकार

बता दें कि इसी साल जून में देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि ऐसा संभव नहीं है। केंद्र ने कहा था कि कोविड-19 के पीड़ितों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सरकारी संसाधनों की एक सीमा होती है। केंद्र ने यह भी कहा था कि अगर इस तरह से मुआवजा दिया गया तो वर्ष 2021-22 के लिए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के लिए आवंटित राशि 22184 करोड़ रुपये इस मद में ही खर्च हो जाएंगे और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी। चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि राज्य सरकारों की वित्तीय सामर्थ्य से परे है। पहले से ही राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के वित्त पर भारी दबाव है।

स्थिर ग्रोथ के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की जरूरतः गवर्नर RBI

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि महामारी के बाद आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के साथ साथ छोटे शहरों में रोजगार के नये अवसरों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर और जोर देने की आवश्यकता है। एआईएमए राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर ने सतत वृद्धि और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा, डिजिटल क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं में निवेश बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने उभरते और विकासशील देशों में सबसे ज्यादा गरीबों को प्रभावित किया है। गवर्नर ने कहा, ''हमारा प्रयास महामारी के बाद ऐसी ग्रोथ को सुनिश्चित करने पर होना चाहिये जो टिकाऊ रहे। आने वाले समय में निजी खपत को पटरी पर लाना महत्वपूर्ण होगा। '' आरबीआई गवर्नर के अनुसार इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सतत वृद्धि मध्यम अवधि के निवेश, मजबूत वित्तीय प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों के साथ आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा, ''इस उद्देश्य के लिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इनोवेशन, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश को गति देने की जरूरत है। हमें प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने और महामारी से उत्पन्न अवसरों से लाभ उठाने के लिए श्रम एवं उत्पाद बाजारों में सुधारों को जारी रखा जाना चाहिए।''

इसके साथ ही गवर्नर ने कहा कि कृषि क्षेत्र और बागवानी की उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिये वेयरहाउस और सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी महत्वपूर्ण हैं। इनकी मदद से कस्बों और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होने कहा कि सरकार के द्वारा लाई गई प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिये काफी मददगार साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों की अहमियत की भी बात कही।

श्राद्ध पक्ष में ना करें ऐसे काम

श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो गया है। श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की संतुष्टि हेतु तथा उनकी अनंत तृप्ति हेतु, उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मनुष्य को अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपने पूर्वजों अर्थात पितरों की संपत्ति का उपभोग तो करते हैं, लेकिन उनका श्राद्ध नहीं करते, ऐसे लोग अपने ही पितरों द्वारा अभिशप्त होकर नाना प्रकार के दुखों का भाजन बनते हैं। श्राद्ध करते समय अपराह्न का समय, कुशा, श्राद्धस्थली की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और ब्राह्मण की उपस्थिति, तिल, चावल, जौ, जल, मूल (जड़युक्त सब्जी) और फल आदि कार्य और सामग्री का उपयोग करें। इस दिन पुत्री के पुत्र को भोजन, तिल और नेपाली कंबल ये चीजें शुद्धिकारक मानी गई हैं। अतः इनका ध्यान रखें। आगे जानिए क्या न करें।

श्राद्ध पक्ष में ना करें यह काम

1. श्राद्ध के लिए उचित बातें- सफाई, शांत चित्त, क्रोध न करें और धैर्य से पूजन-पाठ (हड़बड़ी व जल्दबाजी नहीं) करें।
2. श्राद्ध में कदापि न करें- कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में प्रयुक्त नहीं होते- मसूर, राजमा, कोदो, चना, कपित्थ, अलसी, तीसी, सन, बासी भोजन और समुद्र जल से बना नमक। भैंस, हिरणी, ऊंटनी, भेड़ और एक खुर वाले पशु का दूध भी वर्जित है, पर भैंस का घी वर्जित नहीं है।
3. श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष तुष्टिकारक माने जाते हैं।
4. श्राद्ध किसी दूसरे के घर में, दूसरे की भूमि में कभी नहीं किया जाता है। जिस भूमि पर किसी का स्वामित्व न हो, सार्वजनिक हो, ऐसी भूमि पर श्राद्ध किया जा सकता है।
5. तेल मालिश, दाढ़ी, बाल न कटवाएं, ये कार्य ना करें।
6. ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें।
7. किसी दूसरे के घर अथवा बाहर भोजन ना करें।

श्राद्ध पक्ष : क्या होता है तर्पण और पिंडदान करना, खुद ही कैसे करते हैं ये कर्म, जानिए

इस बार पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष 20 सितंबर 2021, सोमवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होंगे। पितृ पक्ष का समापन 6 अक्टूबर 2021, बुधवार को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। श्राद्ध पक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान कैसे करें इस संबंध में सामान्य विधि यहां पढ़िये।

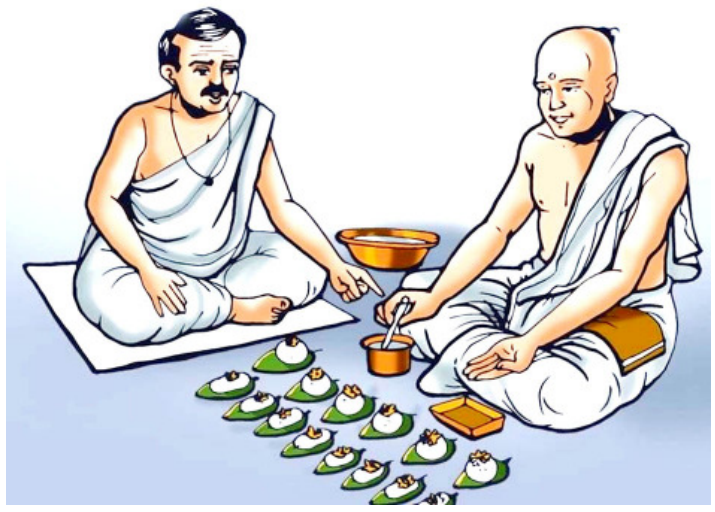

तर्पण :

किसे कहते हैं तर्पण : तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। पितरों के लिए किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध तथा तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार : तर्पण के 6 प्रकार हैं- 1. देव-तर्पण 2. ऋषि-तर्पण 3. दिव्य-मानव-तर्पण 4. दिव्य-पितृ-तर्पण 5. यम-तर्पण 6. मनुष्य-पितृ-तर्पण। सभी के के लिए तर्पण करते हैं।

कैसे करते हैं तर्पण :

1. पितृ पक्ष में प्रतिदिन नियमित रूप से पवित्र नदी में स्नान करने के बाद तट पर ही पितरों के नाम का तर्पण किया जाता है। इसके लिए पितरों को जौ, काला तिल और एक लाल फूल डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खास मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना होता है।
2. सर्वप्रथम अपने पास शुद्ध जल, बैठने का आसन (कुशा का हो), बड़ी थाली या ताम्रण (ताम्बे की प्लेट), कच्चा दूध, गुलाब के फूल, फूल-माला, कुशा, सुपारी, जौ, काली तिल, जनेऊ आदि पास में रखे। आसन पर बैठकर तीन बार आचमन करें। ॐ केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः बोलें।
3. आचमन के बाद हाथ धोकर अपने ऊपर जल छिड़के अर्थात् पवित्र होवें, फिर गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर कुशे की पवित्री (अंगूठी बनाकर) अनामिका अंगुली में पहन कर हाथ में जल, सुपारी, सिक्का, फूल लेकर निम्न संकल्प लें।
4. अपना नाम एवं गोत्र उच्चारण करें फिर बोले अथ् श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थ देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणम करिष्ये।।
5. इसके बाद थाली में जल, कच्चा दूध, गुलाब की पंखुड़ी डाले, फिर हाथ में चावल लेकर देवता एवं ऋषियों का आह्वान करें। स्वयं पूर्व मुख करके बैठें, जनेऊ को रखें। कुशा के अग्रभाग को पूर्व की ओर रखें, देवतीर्थ से अर्थात् दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से तर्पण दें, इसी प्रकार ऋषियों को तर्पण दें।
6. अब उत्तर मुख करके जनेऊ को कंठी करके (माला जैसी) पहने एवं पालकी लगाकर बैठे एवं दोनों हथेलियों के बीच से जल गिराकर दिव्य मनुष्य को तर्पण दें। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को जल अर्पण किया जाता है।
7. इसके बाद दक्षिण मुख बैठकर, जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाए, थाली में काली तिल छोड़े फिर काली तिल हाथ में लेकर अपने पितरों का आह्वान करें- ॐ आगच्छन्तु में पितर इमम ग्रहन्तु जलान्जलिम। फिर पितृ तीर्थ से अर्थात् अंगूठे और तर्जनी के मध्य भाग से तर्पण दें।
8. तर्पण करते वक्त अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें, गोत्रे अस्मत्पितामह (पिता का नाम) वसुरूपत् तृप्यतमिदं तिलोदकम गंगा जलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र से पितामह और परदादा को भी 3 बार जल दें। इसी प्रकार तीन पीढ़ियों का नाम लेकर जल दें। इस मंत्र को पढ़कर जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें।
9. जिनके नाम याद नहीं हो, तो रूद्र, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का नाम उच्चारण कर लें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाए। फिर कंडे पर गुड़-घी की धूप दें, धूप के बाद पांच भोग निकालें जो पंचबली कहलाती है।
10. 9. इसके बाद हाथ में जल लेकर ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः बोलकर यह कर्म भगवान विष्णु जी के चरणों में छोड़ दें। इस कर्म से आपके पितृ बहुत प्रसन्न होंगे एवं मनोरथ पूर्ण करेंगे।

पिंडदान

किसे कहते हैं पिंडदान : चावल को गलाकर और गलने के बाद उसमें गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर गोल-गोल पिंड बनाए जाते हैं। जनेऊ को दाएं कंधे पर पहनकर और दक्षिण की ओर मुख करके उन पिंडो को पितरों को अर्पित करने को ही पिंडदान कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि चावल से बने पिंड से पितर लंबे समय तक संतुष्ट रहते हैं।

पहले तीन पिंड बनाते हैं। पिता, दादा और परदादा। यदि पिता जीवित है तो दादा, परदादा और परदादा के पिता के नाम के पिंड बनते हैं।

1. तर्पण या पिंडदान करते समय सफेद वस्त्र पहने जाते हैं और दोहपहर में ही यह क्रिया करें।
2. पहले पिंड को तैयार कर लें और फिर चावल, कच्चा सूत्र, मिठाई, फूल, जौ, तिल और दही से उसकी पूजा करें। पूजा करते वक्त अगरबत्ती जलाएं।
3. कम से कम तीन पीढ़ी का पिंडदान करें।
4. पिंड को हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप करते हुए, 'इदं पिण्ड (पितर का नाम लें) तेभ्यः स्वधा' के बाद पिंड को अंगूठा और तर्जनी अंगुली के मध्य से छोड़ें।
5. पिंडदान करने के बाद पितरों का ध्यान करें और पितरों के देव अर्यमा का भी ध्यान करें।
6. अब पिंडों को उठाकर ले जाएं और उन्हें नदी में प्रवाहित कर दें।
7. पिंडदान के बाद पंचबलि कर्म करें। अर्थात पांच जीवों को भोजन कराएं। गोबलि, श्वान बलि, काकबलि, देवादिबलि और पिपलिकादि। गोबलि अर्थात गाय को भोजन, श्वान बलि अर्थात कुत्ते को भोजन, काकबलि अर्थात देवी और देवताओं को भोग लगाना, पिपलि बलि अर्थात पीपल के पेड़ में भोजन को अर्पण करना।

पितृ पक्ष : पितरों के श्राद्ध के लिए हैं ये 12 प्रमुख स्थान

पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले कर्म तर्पण, भोज और पिंडदान को उचित रीति से नदी के किनारे किया जाता है। इसके लिए देश में कुछ खास स्थान नियुक्त हैं। देश में श्राद्ध पक्ष के लिए लगभग 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है जिनमें से 12 स्थान सबसे खास माने गए हैं।

1. **उज्जैन (मध्यप्रदेश) :** उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्धवट पर श्राद्ध कर्म के कार्य किए जाते हैं।
2. **लोहानगर (राजस्थान) :** इसे लोहार्गल कहते हैं। यहां पांडवों ने अपने पितरों के लिए सुरजकुंड में मुक्ति का कार्य किया था। यहां खासकर अस्थि विसर्जन होता है। यहां तीन पर्वत से निकलने वाली सात धाराएं हैं।
3. **प्रयाग (उत्तर प्रदेश) :** त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है।
4. **हरिद्वार (उत्तराखंड) :** यहां हर की पौड़ी पर सप्त गंगा, त्रि गंगा और शकावर्त में मुक्ति कर्म किया जाता है।
5. **पिण्डारक (गुजरात) :** पिंडारक प्राभाष क्षेत्र में द्वारिका के पास एक तीर्थ स्थान है। यहां पितृ पिंड सरोवर है।
6. **नाशिक (महाराष्ट्र) :** यहां गोदावरी नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है।
7. **गया (बिहार) :** गया में फल्गु नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है।
8. **ब्रह्मकपाल (उत्तराखंड) :** कहते हैं जिन पितरों को गया में मुक्ति नहीं मिलती या अन्य किसी और स्थान पर मुक्ति नहीं मिलती उनका यहां पर श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है। यह स्थान बद्रीनाथ धाम के पास अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है।

9. **मेघंकर (महाराष्ट्र) :** यहां पैनगंगा नदी के तट पर मुक्ति कर्म किया जाता है।
10. **लक्ष्मण बाण (कर्नाटक) :** यह स्थान रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मण मंदिर के पीछे लक्ष्मण कुंड है जहां पर मुक्ति कर्म किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहां पर श्रीराम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था।
11. **पुष्कर (राजस्थान) :** यहां पर बहुत ही प्राचीन झील है जिसके किनारे मुक्ति कर्म किया जाता है।
12. **काशी (उत्तर प्रदेश) :** काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। चेतगंज थाने के पास पिशाच मोचन कुंड है जहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध करने से पितरों को प्रेत बाधा और अकाल मृत्यु से मरने के बाद अन्य तरह की व्याधियों से भी मुक्ति मिल जाती है।

पुराणों अनुसार ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गोशाला में मृत्यु तथा कुरुक्षेत्र में निवास- ये चारों मुक्ति के साधन हैं- गया में श्राद्ध करने से ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरुपत्नीगमन और उक्त संसर्ग-जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। अंतिम श्राद्ध ब्रह्मकपाल में होता है।

फॉरएवरमार्क का अवंती जूलरी कलेक्शन लांच

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने अपने नवीनतम जूलरी कलेक्शन को लॉन्च कर दिया है। फॉरएवरमार्क अवंती जोशीली उम्मीदों का एक ऐसा खजाना है, जो पहनने वाले व्यक्ति को अपनी शक्ति का एहसास करने तथा हर दिन अपना टिकाऊ असर पैदा करने की प्रेरणा देता है। फॉरएवरमार्क अवंती जूलरी कलेक्शन का हर आभूषण किसी तरंग की तरह लहराता है, जो कोई नई शुरुआत होने का प्रतीक है। असाधारण छत्तीस प्रकार के आभूषणों में से हर एक के मध्य में 0.10, 0.18 और 0.30 कैरेट का एक दुर्लभ डी बीयर्स फॉरएवरमार्क हीरा जड़ा हुआ है। इस कलेक्शन में 18 कैरेट सोने की पीले, सफेद या सुनहरे गुलाबी रंग में जड़ाऊ हीरों वाली स्पष्ट, गोलाकार डिजाइन भी अतिरिक्त खूबसूरती के साथ उपलब्ध हैं। इन अंगूठियों, झुमकों, पेंडेंट और ब्रेसलेट को चाहे अकेले पहनिए या किसी दूसरी जूलरी के साथ पहनिए, ये आपकी स्टायल में जोश भरते हुए आपका आत्मविश्वास छलका देंगे।

'ग्लोबल फॉरएवरमार्क अवंतीरू कलेक्शन को दुर्लभ और कुदरती डी बीयर्स फॉरएवरमार्क हीरों से तैयार किया गया है। कलेक्शन का हर आभूषण इन्हें पहनने वाले व्यक्तियों का निजी प्रतिनिधित्व करता है और उनको याद दिलाता है कि वे मात्र एक छोटी-सी तरंग उठाकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस कलेक्शन का साथ देने के लिए डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने फॉरएवरमार्क अवंतीरू अभियान शुरू किया, जो इस बात की याद दिलाता है कि यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं और हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो आप अपराजेय बन सकते हैं।'- कहना है डी बीयर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सचिन जैन का।

इस जूलरी कलेक्शन का साथ देने के लिए डी बीयर्स फॉरएवरमार्क ने अपना फॉरएवरमार्क अवंतीरू अभियान प्रस्तुत किया है। अभियान इसी विश्वास से प्रेरित है कि भविष्य के गर्भ में जो कुछ भी मौजूद है, वह मात्र एक छोटी-सी तरंग से जाहिर हो सकता है। यह अभियान इस बात की तगड़ी याद दिलाता है कि आज जिन पलों को हम पूरी तरह से जीते हैं, वे कल की बेरोक रफ्तार बन सकते हैं। एक अनूठी विजुअल स्टायल से काम लेते हुए फॉरएवरमार्क अवंतीरू अभियान 'द फर्स्ट रिपल' संभावना की शक्ति का जश्न मनाता है और महिलाओं को दुनिया पर खुद की तरंग छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।

20W के दमदार स्पीकर के साथ लॉन्च हुई Redmi की धांसू Smart TV, कीमत 16 हज़ार से भी कम...

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

शियोमी ने भारत में अपनी नई रेडमी स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दी है। ये टीवी दो स्क्रीन साइज़ 32 इंच और 43 इंच के साथ आती हैं, जिसे कंपनी ने एक ऑनलाइन इवेंट द्वारा पेश किया गया है। शियोमी की नई टीवी की सबसे खास बात यह है कि ये टीवी एंड्रॉयड 11 पर काम करता है, और इस समय में कोई भी टीवी इस ध्ए पर कोई काम टीवी नहीं काम करती है। इसके अलावा इसमें क्रोमकास्ट बिल्ट-इन और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें बाकी ज़रूर फीचर के तौर पर इसमें डुअल बैंड ेंग, 20ें स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो साउंड मिलता है।

रेडमी स्मार्ट टीवी की शुरुआती कीमच 15,999 रुपये है, जो कि इसके 32 इंच टीवी की है। वहीं इसकते 43 इंच मॉडल की कीमत 25,999 रुपये रखी गई है। शियोमी ने टीवी की सेल डेट के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन ऐलान हुआ है कि Mi पर दिवाली के पहले दिन और अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। शियोमी फेस्टीव सीज़न के सिए इसपर स्पेशल सेल प्राइज़ भी देगी, लेकिन फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। नई Redmi Smart TV दो स्क्रीन साइज़ 32-inch और 43-inch में आती है। इसका 32-इंट वेरिएंट HD डिस्प्ले और इसका 43-inch वेरिएंट फुल HD डिस्प्ले के साथ आएगा। शियोमी ने अपने टीवी नें कस्टमाइज़ पिक्चर कंट्रोल दिया है। इसमें कनेक्टिविटी के तौर पर HDMI, 3.5mm जैक, USB, AV, Ethernet और Antenna पोर्ट दिए गए हैं।

एंड्रॉयड 11 पर काम करती है नई Smart TV...

शियोनी की ये नई स्मार्ट TV एंड्रॉयड 11 के साथ पैचवॉल UI 4 पर काम करेगी। शियोमी की कस्टम स्किन को हाल ही में Mi TV 5X के साथ पेश किया है। इसमें IMDb इंटीग्रेशन मौजूद हैस जिससे व्यूअर्स डायरेक्ट कंटेंट पेज से शोज़ और मूवी की रेटिंग देख सकेंगे। रेडमी स्मार्ट टीवी में 20W स्पीकर्स के साथ आती हैं, जो डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करता है। ऑडियो सिस्टम DTS वर्चुअस के साथ आता है। बाकी फीचर्स के तौर पर इसमें डुअल बैंड, Wifi, ब्लूटूथ 5.0, ऑटो लो लेटेंसी मोड और कई खासियत मौजूद हैं। इसका डिस्प्ले वीविड पिक्चर इंजन का इस्तेमाल करेगा, और टीवी शियोमी के Make In India का हिस्सा है।

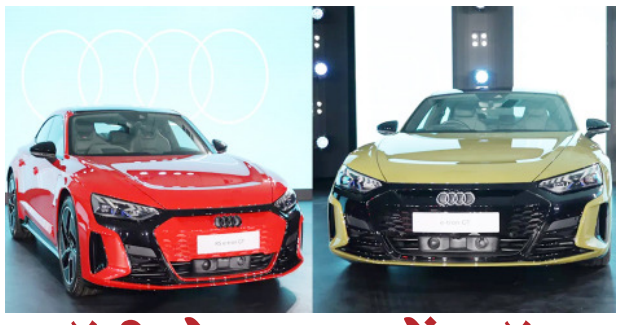

ऑडी ने भारत में लॉन्च की दो इलेक्ट्रिक कार

3.3 सेकेंड में पकड़ लेती हैं 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी ऑडी ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों के प्रति बढ़ती रुचि के बीच बुधवार को अपनी दो इलेक्ट्रिक 'सुपरकारों' ई-ट्रॉन जीटी (और आरएस ई-ट्रॉन जीटी को भारतीय बाजार में उतारने की घोषणा की। कंपनी ने अनुसार ई-ट्रॉन जीटी एडिशन की कीमत 1.79 करोड़ रुपये और आरएस ई-ट्रॉन जीटी एडिशन की कीमत 2.04 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम) रखी गई है। खास बात यह है कि यह दोनों गाड़ियां 5 से 80 फीसदी तक केवल 22 मिनट में चार्ज हो सकती है।

Audi RS e-tron GT महज 3.3 सेकेंड में पकड़ लेती हैं 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार

ऑडी ने बताया कि ई-ट्रॉन जीटी 390 किलोवाट की बैटरी से लैस हैं और 4.1 सेकेंड में शून्य से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार पकड़ सकती है, जबकि 475 किलोवाट की क्षमता के साथ आने वाली आरएस ई-ट्रॉन जीटी मात्र 3.3 सेकंड में इतनी ही गति हासिल कर सकती है। एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चल सकती है Audi RS e-tron GT। कंपनी ने कहा कि एक बार पूरी बैटरी चार्ज करने के बाद ई-ट्रॉन जीटी 401 से 481 किमी की दूरी तय कर सकती है। वही आरएस ई-ट्रॉन जीटी एक बार चार्ज होने के बाद 388 किमी से 500 किमी तक चल सकती है। इस अवसर पर ऑडी इंडिया के प्रमुख बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि यह दिन हमारे लिए मील का पत्थर है क्योंकि हम भारत की पहली इलेक्ट्रिक सुपरकार पेश कर रहे हैं। जुलाई 2021 के बाद से यह हमारा चौथा और पांचवां इलेक्ट्रिक वाहन हैं।

सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए 30 करोड़ 73.3 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र ने जून में समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए 30 करोड़ 73.3 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के रिकॉर्ड 30 करोड़ 86.5 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 3.74 प्रतिशत अधिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रबी अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान चालू फसल वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों का पूरा समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन और वर्षा सिंचित खेती से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तोमर ने राज्यों से पानी, बिजली और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और नैनो-यूरिया का उपयोग करने का आग्रह किया जो भूमि की उर्वरता के लिए कम खर्चीला और फायदेमंद है। मंत्री ने कहा कि केवीके (कृषि विज्ञान केंद्र) को छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए ताकि वे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीएम किसान और केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान तक पहुंचे।

सरकार ने फसल वर्ष 2021-22 के लिए 30 करोड़ 73.3 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्र ने जून में समाप्त होने वाले चालू फसल वर्ष 2021-22 के लिए 30 करोड़ 73.3 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य फसल वर्ष 2020-21 के रिकॉर्ड 30 करोड़ 86.5 लाख टन के अनुमानित उत्पादन से थोड़ा कम है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन से 3.74 प्रतिशत अधिक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रबी अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान चालू फसल वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्यों का पूरा समर्थन करेगा। उन्होंने कहा कि यह जलवायु परिवर्तन और वर्षा सिंचित खेती से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में राज्यों की मदद करने के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तोमर ने राज्यों से पानी, बिजली और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और नैनो-यूरिया का उपयोग करने का आग्रह किया जो भूमि की उर्वरता के लिए कम खर्चीला और फायदेमंद है।

सरकार ने मोती की खेती के लिये झारखंड की कंपनी से भागीदारी की

नयी दिल्ली। एजेंसी

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मोती की खेती के लिये अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रशिक्षण देने को लेकर झारखंड की कंपनी के साथ भागीदारी की है। मंत्रालय के अधीन आने वाली एजेंसी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड) ने इसके लिये पूर्ति एग्रोटेक के साथ सोमवार को समझौता किया। यह कंपनी जनजातीय समुदाय से आने वाले उद्यमी बुद्धन सिंह पूर्ति की है। ट्राइफेड का काम जनजातीय समुदाय द्वारा बनाये गये उत्पादों का विपणन और संवर्धन करना है। मंत्रालय की झारखंड में वन धन विकास केंद्र के 25 संकुलों के विकास की योजना है। इसके तहत मोती की खेती शामिल की जा सकती है। वन धन विकास केंद्र कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना का केंद्र है।

सतत आर्थिक वृद्धि के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश की जरूरतः दास

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि सतत आर्थिक वृद्धि और छोटे शहरों में रोजगार सृजित करने के लिये बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के साथ शिक्षा तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की जरूरत है। दास ने कहा, ''ऐसे समय जब हम महामारी से उबर रहे हैं, हमें मौजूदा संकट से निपटना होगा और मजबूत, समावेशी तथा सतत वृद्धि के लिये बेहतर परिवेश बनाना होगा संकट ने जो नुकसान पहुँचाया है, उसे सीमित करना केवल पहला कदम था। महामारी के बाद के समय में हमारा प्रयास टिकाऊ और सतत वृद्धि सुनिश्चित करना होना चाहिए।'' आरबीआई गवर्नर ने वीडियो कांफ्रेन्स के जरिये 48वें एआईएमए राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सतत वृद्धि मध्यम अवधि के निवेश, मजबूत वित्तीय प्रणाली और संरचनात्मक सुधारों के जरिये वृहत आर्थिक बुनियाद को मजबूत किया जाना चाहिए। दास ने कहा,''इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, नवप्रर्वतन, भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा की जरूरत होगी। हमें प्रतिस्पर्धा और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने तथा महामारी से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिये श्रम तथा उत्पाद बाजारों में भी सुधारों को जारी रखना चाहिए।''

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कृषि और बागवानी क्षेत्र में मूल्य वर्धन और उत्पादकता बढ़ाने को लेकर गोदाम तथा आपूर्ति व्यवस्था से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी महत्वपूर्ण है। इससे छोटे शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होंगे तथा समावेशी वृद्धि को बढ़वा मिलेगा। दास ने कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा हाल में

कुछ क्षेत्रों के लिये घोषित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना महत्वपूर्ण पहल है। इस पहल से प्राप्त लाभ टिकाऊ होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने उभरते और विकासशील देशों में सबसे ज्यादा गरीब और वंचित तबकों को प्रभावित किया है। दास ने कहा, ''हमारा प्रयास महामारी बाद के समय में रहने योग्य और टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने का होना चाहिए। आने वाले समय में निजी खपत को टिकाऊ रूप से पटरी पर लाना महत्वपूर्ण होगा। यह ऐतिहासिक रूप से समग्र मांग का मुख्य आधार रहा है।'' आरबीआई गवर्नर के अनुसार महामारी के बाद की दुनिया में समावेशी वृद्धि के लिये सभी पक्षों के सहयोग और भागीदारी की जरूरत है। विभिन्न पक्षों की भागीदारी के प्रयास से ही तेजी से टीकाकरण के कठिन कार्य को पूरा करने में मदद मिल रही है।

उन्होंने कहा कि महामारी के बाद की दुनिया में समावेश के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती स्वचालन से आएगी। स्वचालन बढ़ने से कुल मिलाकर उत्पादकता बढ़ेगी लेकिन इससे श्रम बाजार पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे परिदृश्य में कार्यबल के कौशल/प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दास ने यह भी कहा कि महामारी के बाद डिजिटलीकरण में तेजी आई है लेकिन डिजिटल अंतर उभरने से बचने की जरूरत है।

आरबीआई गवर्नर ने सतत वृद्धि के लिये हरित भविष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, ''स्वच्छ और दक्ष ऊर्जा प्रणाली, आपदा के नजरिये से मजबूत बुनियादी ढांचा और सतत पर्यावरण की आवश्यकता पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियों को अपनाते समय देश की विशेषताओं और उनके विकास के चरण को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग देश की रूपरेखा पर उचित विचार किया जाना चाहिए।'' उन्होंने भारत की प्रतिस्पर्धी क्षमता का जिक्र करते हुए कहा कि देश में यूनिकार्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप) की संख्या बढ़ रही है। यह प्रौद्योगिकी आधारित संभावनाओं को बताता है। दास ने कहा कि ई-वाणिज्य एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो बढ़ते बाजार, इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच बढ़ने तथा कोविड महामारी के कारण उपभोक्ताओं के पंसद में बदलाव से लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्किल इंडिया और नवोन्मेष कोष जैसे सरकार की विभिन्न पहल से डिजिटल क्षेत्र में तेजी से विकास के लिए एक अनुकूल परिवेश बना है। दास ने कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था के लिये गतिशील और ठोस वित्तीय प्रणाली की जरूरत होती है। भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिये वित्तीय प्रणाली में तेजी से बदलाव आया है।

एसबीआई, पीएनबी के बाद अब एचडीएफसी ने सस्ता किया होम लोन, जानें ब्याज की नई दरें

नई दिल्ली। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। दुर्गापूजा, दिवाली में लोग नए घर खरीदने की प्लानिंग करते हैं। अगर आप भी इस दशहरा, दिवाली पर घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक के बाद अब निजी सेक्टर के बैंक एचडीएफसी बैंक ने भी होम लोन ब्याज दरों में गिरावट की है।

सस्ता हुआ लोन निजी सेक्टर के बैंक एचडीएफसी ने ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक ने त्योहारों को देखते हुए होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि को सस्ता कर दिया है। बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती के साथ-साथ कई नए ऑफर्स लॉन्च किए हैं। प्ऊइण बैंक ने लोन की ब्याज दरों को घटाकर 6.70 फीसदी कर दिया है। आप बैंक के इस स्पशेल ऑफर के साथ 6.70 फीसदी की शुरुआती दर से होम लोन ले सकते हैं। आपको बता दें कि ये ऑफर सिर्फ नया लोन अप्लाई करने वाले ग्राहकों पर ही लागू होगा। वर्तमान में यहां एचडीएफसी के होम लोन की शुरुआती ब्याज दर 6.75 फीसदी है, उसे अब घटाकर 6.70 फीसदी कर दिया गया है। 31 अक्टूबर तक ऑफर बैंक ने कहा हैं बैंक का ये ऑफर सिर्फ नए कर्जधारकों पर ही लागू होगा। बैंक ने इस ऑफर के तहत नया लोन लने वालों को कम दरों पर होम लोन मिलेगा। आपको बता दें कि होम लोन की ब्याज दर लोन की राशि, लोन धारक के क्रेडिट स्कोर , लोन के टेन्योर पर निर्भर करता है। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा, ब्याज की दर भी उतनी बेहतर होगी। बैंक के इस ऑफर का लाभ आप 31 अक्टूबर तक उठा सकते हैं।

इन बैंकों ने भी घटाई ब्याज दर आपको बता दें कि एचडीएफसी बैंक से पहले कई बैंकों ने ब्याज दरों में कटौती की है। एसबीआई ने भी बैंक की ब्याज दर में कटौती की है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने यहां कर्ज को सस्ता कर दिया है।

पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 की गई

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अगर आपने अभी तक अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ा है तो आपको और वक्त मिल गया है। आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। यानी पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा को छह माहीने बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों हो रही कठिनाई को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी

गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा भी 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी आप www.incometaxindia.gov.in. पर जाकर भी ले सकते है।

पैन कार्ड में क्या क्या होती हैं जानकारियां

पैन कार्ड में आपका नाम, अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, सिग्नेचर जैसी जानकारियां होती हैं। इसके साथ ही ये फोटो पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल होता है। इसी कार्ड के आधार पर दी गयी जानकारियां आगे इस्तेमाल की जाती है। अगर पैन कार्ड में दी गयी जानकारियों में कोई गलती है। या फिर आप उन्हें सुधारना चाहते हैं तो ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं।

अगर आपका पता भारत का है तो पैन करेक्शन के लिए 100 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी. वहीं, जिन लोगों का एड्रेस भारत से बाहर का है, उन्हें 1011 रुपए की फीस देनी होगी. यहां पेमेंट के लिए अलग-अलग ऑप्शन होते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और डिमांड ड्राफ्ट. पेमेंट के बाद उसकी रसीद का प्रिंट ले लें।

स्टेशनों पर मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा, IRCTC शुरू करेगी एग्जीक्यूटिव लाउंजः सूत्र

नई दिल्ली। एजेंसी

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा देगी। इसके लिए की एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू करने की योजना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईआरसीटीसी 12 और शहरों में एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरु करेगी । सूत्रों के मुताबिक IRCTC की एग्जीक्यूटिव लाउंज में स्पा, लाइब्रेरी शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आईआरसीटीसी 12 और शहरों में एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरु करेगी और इन नए शहरों में पटना, वाराणसी, लखनऊ चंडीगढ़ शामिल होगे। जानकारी के मुताबिक IRCTC की इस एग्जीक्यूटिव लाउंज में मल्टी कुजिन भी होगा । सूत्रों के अनुसार इस एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने में 2-4 करोड़ रुपये की लागत लगेगी जबकि लाउंज से IRCTC सालाना 60-70 लाख रुपये तक की कमाई करने का अनुमान लगा रही है। सूत्रों के अनुसार 6 महीने में ध्ंऊण की इन स्टेशनों पर 25 फूड प्लाजा खोलने की भी योजना है। 22 सितंबर यानी आज के कारोबार में आईआरसीटीसी के स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। एनएसई आज यह शेयर 46.75 रुपये यानी 1.29 फीसदी की बढ़त के साथ 3671.80 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बीएसई पर यह शेयर 46.25 रुपये यानी 1.28 फीसदी की बढ़त के साथ 3671 के स्तर पर बंद हुआ है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।